per month in local calls. The result of the study showed the following effective charge per minute in respect of operators with the lowest tariff in each of the categories for fixed service, WLL (M) and cellular service. This is based on data furnished by service providers on 30.6.2003 in their Quarterly Report to TRAI.

Fixed	:	Re.0.78
WLL(M)	:	Re. 0.67
Cellular	:	Rs. 1.12

Cellular operators are offering a variety of long distance tariff packages. The lowest rate per minute for a domestic long distance call from a mobile phone is less than the rate applicable for calls from fixed phones.

(c) The percentage of people using mobile services in the country is around 2.3%. This includes both cellular services and WLL (M) services.

New licence regime

†*244. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether by introducing 'unified licence' Government are migrating to a new licence regime;

(b) if so, whether Government are working out a miniumum reserve price for the licenses based on valuation of spectrum; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ARUN SHOURIE): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) No,Sir. Based upon the recommendations of Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), the prescribed entry fee for Unified Access Services Licence (UASL) is equal to the entry fee paid by the 4th

†Question No. 241 and 244 were taken together.

Cellular Operators where such an Operator is present. Where no such operator is present the entry fee is equal to the entry fee fixed by the Government for the Basic Service Operators (BSOs). The entry fee for migration of the BSOs (with or without Wireless in Local Loop facility) to UASL is equal to the entry fee paid by the fourth Cellular Operator for that service area, or the entry fee paid by the BSO itself, whichever is higher. No entry fee is to be paid by the existing Cellular Operators for migration to UASL. In addition, the Unified Access Services Licensee will be required to pay annual licence fee as a percentage of 'Adjusted Gross Revenue' as well as separate charges for the use of the spectrum.

डा॰ प्रभा ठाकुर: माननीय सभापति जी, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी की तरफ से जवाब दिया गया है कि सेल्युलर आपरेटरों द्वारा अनेक प्रशुल्क पैकेज देने के कारण बुनियादी और मोबाइल फोनों के घरेलू टेलीफोन प्रशुल्कों की तुलना करना बहुत कठिन है। मेरा प्रश्न यह था कि क्या घरेलू फोन की दर मोबाइल फोन की तुलना में अधिक है? यह बड़े अफसोस की बात है और महोदय, यह एक विचारणीय विषय है कि जबकि एक ओर प्राइवेट सेल्युलर कंपनियां लगातार आगे बढ़ रही हैं, मुनाफा कमा रही हैं। और सेल्युलर कंपनियां जो कि सरकार की संचार इनकम की सेवाओं की सीढ़ी लगाकर तरक्की कर रही हैं और आगे बढ़ गई हैं,वहां हमारी जो संचार सेवाएं हैं, वे लगातार मुनाफे की दृष्टि से पिछड़ती जा रही हैं और स्थिति यहां तक आ गई है कि वी एस एन एल के जो ग्रहक हैं, हर माह औसतन तीन लाख लोग कनेक्शन कटवा रहे हैं। यह स्थिति क्यों है और क्या कारण है कि प्राइवेट कंपनियां जो सेल्युलर सेवा दे रही हैं, उनसे वी एस एन एल और एम टी एन एल कंपनियां कंपीटीशन में पिछड़ रही हैं?

श्री अरुण शौरी: सर पहली बात यह है कि कंपीटीशन के कारण जो रेट हैं, ये बहुत ज्यादा कोलैप्स करते हैं। सेल्युलर रेट्स जैसा कि मैम्बर ने कहा, कुछ ही साल हुए यह सेल्युलर रेट 16 रुपए प्रति मिनट था, आज वह 1रुपए 70 पैसे प्रति मिनट हो गया है कंपीटीशन के कारण और यह सोचना कि आज कंपैरिजन किया जाए तो कोई 400 या 450 ऐसे alternate पैकेज हरेक सर्विस प्रोवाइडर ने और वी एस एन एल तक ने दे रखे हैं।- तो उनका कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल होता है। काल फिक्स्ड लाइन से डब्ल्यू एल एल को जाए, काल फिक्स्ड लाइन सेल्युलर को जाए इन सबके रेट डिफरेंट होते हैं। सीजन में रेट डिफरेंट होते हैं। अभी रमजान में कई आरपेटर्स ने मिडिल ईस्ट की काल्स के लिए कंसेशन किए अभी बी एस एन एल ने दिसंबर जनवरी के लिए साउथ ईस्ट एशिया के लिए यू के के लिए यूरोप के लिए अमेरिका के लिए विभिन्न प्रमोशनल स्कीम्स निकाली। इसलिए कंपैरिजन करना मुश्किल है। ट्राइ ने 400 मिनट लोकल काल्स के लिए सर्वे किया कि 400 मिनट के लिए कितना एवरेज कास्ट होती है, उसका रिजल्ट मैंने बताया है क्योंकि फिक्स्ड काल्स के रेट कम हैं और सेल्युलर के ज्यादा हैं।

सर, दूसरी चीज उन्होंने कही कि बी॰एस॰एन॰एल॰ पिछड़ता जा रहा है सेल्युलर के कंपैरिजन में। यह बात बिलकुल ही गलत है क्योंकि अभी एक ही साल हुआ है जब बी एस एन एल की सेल्युलर सर्विस शुरू हुई थी और एक साल में यह देश के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने 43 लाख कस्टमर्स अपनाए हैं और इनसे डिमांड होती है कि ''सेल वन'' सर्विस हमारे एरिया में आए। तो आप विश्वस्त रहिए कि बी एस एन एल रेट्स में भी बिलकुल पेस सेट कर रहा है। सेल्युलर आपरेटर मेरे पास आए हैं कि अगर आप बी एस एन एल पर लगाम नहीं लगाओगे तो हम खत्म हो जाएंगे क्योंकि वे रेट्स में कंपैरिजन कर रहे हैं।

डा॰ प्रभा ठाकुर: सर, यह ''राष्ट्रीय सहारा'' की 3 दिसम्बर की न्यूज है जिसमें लिखा है कि बी एस एन एल के उपभोक्ताओं में हर माह औसतन तीन लाख ग्राहक कनेक्शन कटवा रहे हैं- इसके आधार पर मैंने यह बात कही थी।

मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न यह है कि देश में कितने प्रतिशत लोग मोबाइल सेवा का उपयोग कर रहे हैं? माननीय सभापति जी, आज भी इस देश में अधिकांश लोग गांवों में, कस्बों में, छोटे शहरों में बेसिक घरेलू फोन पर निर्भर करते हैं, मोबाइल सेवा पर नहीं। तो यह एक वाकयी अफसोसजनक स्थिति है कि उत्तर में आया है कि लंबी दूरी के विभिन्न पैकेज के तहत मोबाइल फोन से घरेलू फोन पर काल की दर फिक्स्ड फोन की दर से कम है, लेकिन यह क्यों कम है? जो विभिन्न पैकेज प्राइवेट सेल्युलर कंपनियां दे रही हैं, उनके मुकाबले सरकार ऐसे पैकेज क्यों नहीं दे सकती है ताकि घरेलू फोन सेल्युलर फोन के मुकाबले सस्ता हो और आम आदमी को उसका लाभ मिले

श्री अरुण शौरी: सभापति जी, पहली चीज तो यह है, आज यह सोचना कि फिक्सड लाइन का ही फोन गरीब आदमी के पास है या मिडिल क्लास आदमी के पास है, यह गलत चीज है। क्योंकि मिडिल क्लास ही उसको अपना रहा है। आप देखिए कि सेल्युलर फोन की तादाद इंडिया में ज्यादा है और अब हर महीने 13 लाख कंज्यूमर्स और ले रहे हैं। Additional subscribers for cellular services are 1.3 million. This is the fastest growth in the world. और ये सिर्फ हमारे इतने अमीर लोग नहीं हैं कि 1.3 मिलियन अमीर ही ले रहे हों। दूसरे, जो फोन सरेंडर हो रहा है, ये इस कारण ही नहीं हो रहा है कि रेट्स ऊपर या नीचे हैं। आज भी सेल्युलर का रेट ज्यादा है। आप उस फिगर को देखिए जो आंसर में दी गई है। हम चाहते हैं कि जहां भी हम हों, चाहे कार में हों, रेस्टोरेंट में हों हम कांटेक्टेबल हों और हम वहां से फोन कर सकें। दूसरे यह कि सेल्युलर सर्विस में तरह-तरह की सर्विसेज अवेलेबल है। उसमें एसएमएस एवेलेबल है, कल वीडियो फोन भी आ जाएगा और ई-मेल अवेलेबल है। आप मेरे फोन पर फैक्स रिसीव कर सकते हैं, फैक्स भेज सकते है। तो इन सब चीजों के कारण फिक्स लाइन से लोग परे जा रहे हैं। सर, मैं इसमें एक ही चीज एड करूंगा कि हम आगे के लिए याद रखें कि फिक्सड् लाइन को लगाना बहुत

एक्सपेंसिव है। कंट्री का फ्यूचर इसमें है कि हम वायरलेस सिगनल को ज्यादा रेंज दे सकें। उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। जब 100-200 मील तक सिगनल जा सकेगा तो वायरलेस के जाल से हर एक लोग के पास मोबाइल हो जाएगा और जो खेत में है, उसके पास भी मोबाइल आयेगा।

MR. CHAIRMAN: Dr. T. Subbarami Raddy.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Q.No. 246.

श्री सभापति: यह 246 नहीं है, यह 241 है।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I will go to Q.No. 246. Today, I have got three questions.

श्री सभापति: अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ। कल आपने मुझ से शिकायत की थी कि आप मुझे सप्लीमेंट्री नहीं करने देते हो। तो ज्यों ही आप आए, मैंने नाम ले दिया। श्री संजय निरुपम।.. ...(व्यवधान)...

SHRI PREM CHAND GUPTA: Sir, Dr. T. Subbarami Reddy informed me that he has only four questions today!

श्री मोती लाल वोरा: सर, आपने यह सुविधा अकेले श्री सुब्बारामी रेड्डी को ही क्यों दे रखी है।

श्री सभापति: यह इसलिए कि मैं जब कहता हूं, ये तभी बोलते हैं और जब कहता हूं कि मत बोलो तो नहीं बोलते।

श्री संजय निरुपम: सभापति महोदय, मेरा पहला निवेदन यह है कि प्रश्न संख्या 241 और 244 लगभग एक ही तरह का प्रश्न है और इन्टर कनेक्टिड है, अगर इन दोनों को क्लब कर दिया जाए तो बहुत सुविधा हो जाएगी। यह नीलोत्पल जी का प्रश्न था।

श्री सभापति: आप इस पर ही बोल लीजिए। इस पर बोलिए, क्लब करना ठीक नहीं है।

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, टेलीकॉम के क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति हो रही है, जो दरें हैं वे निश्चित तौर पर नीचे जा रही हैं। लाइसेंसिंग की पद्धति लगातार बदलती जा रही है। अब तक हमारे देश में टेलीकॉम सेक्टर एनटीपी-99 यानी नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी-99 के हिसाब से रेग्युलेट हो रहा था या चल रहा था। अचानक केबिनेट के फैसले के हिसाब से, मंत्रालय के फैसले के हिसाब से, एनटीपी पॉलिसी को जो प्रोविजन था, जो उसके प्रावधान थे, वे बदल दिए गए हैं और अब यूनिफाइड लाइसेंस यानी अलग-अलग सेक्टर के हिसाब से जो लाइसेंस दिए जाते थे उसके बजाए एक कॉमन लाइसेंस दिया जाता है। मेरा यह कहना है कि एनटीपी पॉलिसी को पूरी तरह से चेंज करने से पहले आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाए? एनटीपी पॉलिसी को पार्लियामेंट में लाया गया था

और उस पर डिसकशन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट या टीडी सेल में जो व्यवस्था है...

श्री सभापति: हो गया क्या?

श्री संजय निरुपम: उन व्यवस्थाओं ने डब्ल्यूएलएल के हिसाब से या फिर जो एक लाइसेंस लिया है वह व्यक्ति उसी लाइसेंस में आपरेट कर सकता है अगर दूसरे लाइसेंस में जाता है तो उसके विरुद्ध में उन लोगों ने अपनी बातें कही थीं। इसके बावजूद उनका विरोध समझने के लिए.....

श्री सभापति: आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री संजय निरुपम: उनके विरोध को समझने के बजाए उनको ठुकराने से पहले अगर एनटीपी-99 के वायलेशन के कार्यक्रम चल रहे थे तो वे उसके लिए पार्लियामेंट में आकर, जो न्यू यूनिफाइड लाइसेंस पॉलिसी है उसको लेकर क्यों नहीं आए और क्यों ये डिसकशन नहीं किया?

श्री अरुण शौरी: सर, मैंने सुना नहीं कि आपने यह इजाजत दे दी हो कि 241 और 244 को क्लब कर दिया जाए। यह तो 244 का क्वेश्चन है। आप चाहें तो मैं जवाब दे देता हूं।

श्री सभापति: 244 किसका है?

श्री संजय निरुपम: सर, 244 का क्वेश्चन है...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: नहीं, वे हैं नहीं।...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए।

श्री अरुण शौरी: सर, मैं तो बहुत चाहूंगा कि डिसकशन वगैरह हो यदि आप एलाऊ करेंगे तो।

श्री सभापति: आप एक का ही जवाब दीजिए। एक का ही जवाब दीजिए।

श्री अरुण शौरी: सर, यह क्वेश्चन लाइसेंसिंग पॉलिसी का है। इन्होंने कहा कि 244 क्लब कर दें। मैं अभी जवाब दे देता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो।

श्री सभापति: मेम्बर हैं नहीं। क्या नीलोत्पल जी आएंगे?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, there is a point of procedure. If you remember, I had brought to your attention one memorandum, from an official of the Department of Communications, informing the Members of Parliament, that the policy has been changed. Now, the question which he is asking relates to that. It is a common thing how the Parliament was not informed! I think that was a point which I had already raised.

श्री सभापति: दूसरा क्वश्चन आप पूछ लीजिए।...(**व्यवधान**)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: That was a very unusual procedure of not informing the Parliament about the policy decision. ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: एक मिनट ठहर जाइये।...(**व्यवधान**)... आप पूछ लीजिए, 244।

श्री दीपांकर मुखर्जी: मैं तो 244 का नहीं हूं।

श्री सभापति: नहीं, वह नीलोत्पल जी हैं नहीं, इसलिए आप पूछ लीजिए।...(**व्यवधान**)... फिर आप जवाब दोनों का दे दीजिए।

SHRI ARUN SHOURIE: Sir, the statement has been placed on the Table of the House. I am happy about the new procedure. Sir, new policies should be welcomed by new procedures of the House!...(*Interruptions*)...

Sir, if I may just give the answer to that, there has been a full consultation on this. टी आर ए आई ने unified licensing policy का जुलाई में कंसल्टेशन पेपर जारी किया और अगस्त तथा सितम्बर में इसकी ओपन हाउस हीयरिंग्ज़ हुईं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्ज़ बनाया अंडर द फाइनांस मिनिस्टर। हमारी रेकमेंडेशन थी कि सात-आठ इश्यूज़ आ गई हैं, कई इश्यूज़ कोर्टस में हैं उस पर गवर्नमेंट कोलैक्टिवली इंटर मिनिस्टीरियल कंसल्टेशंस करके आगे चले। सर, यह तो कहते हैं कि किसी को ठुकराया गया, किसी को ठुकराया नहीं गया। सेलुलर आपरेटर्स अनफॉर्चुनेट्ली जब से यह सैक्टर खुला है, हमेशा कोर्टस में जाते रहे हैं, कभी एक मुद्दा लेकर और कभी दूसरा मुद्दा लेकर। मैं जानता हूं संजय निरुपम कितने कंसर्ड हैं एमटीएनएल के लॉसेज़ से, सरंडर ऑफ् टेलीफोंज़ से। आप जानते हैं सर एमटीएनएल, को जब सेलुलर सर्विस का लाइसेंस दिया गया तो यही सेलुलर एसोसिएशन्स कोर्ट में गई और दो साल तक उनकी सर्विस नहीं चलने दी। उसके बाद नई गाइडलाइंज़ आईं, तब कोर्ट में चले गए। अब भी कोर्ट में चले गए।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: और भी चले जायेंगे।

श्री अरुण शौरी: नहीं, सर। अभी मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हमने जो निर्णय लिए हैं, न्यू लाइसेंसिंग पालिसी में, यूनिवर्सल लाइसेंस ये, दो-तीन साल में इस सैक्टर की शक्ल बदल देंगे। इसी तरह ग्रुप ऑफ् मिनिस्टर्ज़ ने इंटर सर्किल मर्जर्स और इंट्रा-सर्किल मर्जर्स पर जो निर्णय लिए हैं और स्पैक्ट्रम प्राइसिंग स्पैक्ट्रम एलोकेशन पर और जो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ हमने कोआर्डिनेट करके इस सैक्टर के लिए ज्यादा स्पैक्ट्रम अवेलेबल हो, वह काम शुरू किया है, उससे आप देखिए कितना कंपीटिशन होगा और कितना फायदा होगा और लिटीगेशन भी...(**व्यवधान**)... एक सैकंड...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बीच में मत बोलिए। मैं एलाउ नहीं करूंगा।

श्री अरुण शौरी: और जो लिटीगेशन है वह भी इससे कम होगी। इसका एक मैं आपको उदाहरण दे दूं, सर, कि इस बार केस आना था सुप्रीम कोर्ट में और हम तैयार थे, मगर सेलुलर ऑपरेटर्ज़ ने प्ली की कि यह केस पोस्टपोंड कर दिया जाए। उनकी जो कंपेंसेशन वगैरह की मांगें हैं, वे आज फाइनांस मिनिस्टर साहब के सामने हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से हमने अपनी प्रोपोज़ल्ज़ भी उनको दे दी हैं। जैसे ही वे एप्रूव करेंगे, वह सारा पैकेज भी हम एनाउंस कर देंगे।

श्री सभापति: ठीक है। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, जवाब नहीं आया। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: देखिए, जवाब आया या नहीं आया, यह मुझे तय करना है। यह जवाब आ गया है इसमें। ...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: नहीं, सर, जवाब नहीं आया। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: नहीं, आप ऐसा मत कहिए। जवाब आ गया। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरुपम: मैंने पूछा था कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं प्लेस किया जाए ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: हां, यह बता दीजिए। ...(**व्यवधान**)...बस, बात हो गई। देखिए ...(**व्यवधान**)....अब आप बैठिए। आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरुपम: पार्लियामेंट को कंफीडेंस में ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: यह बता दीजिए इनका। ...(**व्यवधान**)...बस हो गई बात, उन्होंने समझ ली है।...(**व्यवधान**)...

श्री अरुण शौरी: सर, जहां तक मुझे याद है एनटीपी पॉलिसी की डिसकशन जरूर हुई थी। ऐसी पॉलिसी स्टेटमेंट्स एजुकेशन पर आती हैं, साइंस पालिसी पर होती हैं, हेल्थ पॉलिसी पर एनाउंस होती हैं, उन पर आप जब चाहिए, मैं तो खुद चाहूंगा कि हमने टेलीकॉम पॉलिसी में रेवाल्यूशनरी स्टैप्स लिए हैं, आप जब चाहेंगे, हम आपके आगे आयेंगे और वह जो एनटीपी 99 थी, उसको अमेंड करके जो सारी चीजें हैं, नोटिफिकेशन...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, it is not a question

of...(*Interruptions*)... This is not the answer to the question raised by him. ...(*Interruptions*)... This is a question of procedure. ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: बस, अब आ गई बात। ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: No, Sir. This is a very basic question. It is a question of parliamentary privilege. NTP was discussed in the Parliament. Now, when there has been a change in the policy, whatever he is saying now ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: It has been discussed. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Whatever he has been saying should have been told, about a change in the policy, first to the Parliament. ...(*Interruptions*)... Why was it not done? ...(*Interruptions*)... Why was it not done?

SHRI ARUN SHOURIE: The Parliament was not in session ...(*Interruptions*)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: That is the question. ...(*Interruptions*).... After the policy was being discussed, what is the idea? ...(*Interruptions*)....

श्री सभापति: आप एक मिनिट सुनिए, डिस्कशन में आप यह समझते हैं कि डिसीजन हुआ था? डिसीजन में कोई चेंज हो ...(**व्यवधान**)... मेरी बात सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)...आप ऐसे मत कीजिए। Please hear me. ....(**व्यवधान**)...

श्री अरुण शौरी: सर, लाइसेंसिंग से इसका ताल्लुक ही नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरुपम: बिल्कुल ताल्लुक है। ...(**व्यवधान**)...

श्री अरुण शौरी: सर, मेंबर साहब जानते नहीं हैं, स्पेक्ट्रम फीस टी॰आर॰ए॰आई॰ डिटरमिन करेगा।

श्री संजय निरुपम: मैं इसे स्पष्ट कर दूं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please listen to me. (Interruptions)... Please listen to me (*Interruptions*)... मेंबर साहब, आप सब जानते हैं।...(**व्यवधान**)...बैठ जाइए।

श्री संजय निरुपम: हमने सेलुलर ऑपरेटर्स को कहा है ...स्पैक्ट्रम फीस देते हैं और उसके बाद लगभग यह एक हजार करोड़ के आसपास आता है ...(**व्यवधान**)...तो पूरे देश में वही ऑपरेशन चार्ज, वही ऑपरेशन फीस, यह 1400 करोड़ में आ रहा है।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य बैठ जाइए। अब अति मत कीजिए। आप भी बैठ जाइए। श्रीमती दुर्गा।

SHRIMATI N.P. DURGA: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether it is true that recently the MTNL has launched three new schemes in its advanced Wireless in Local Loop network. If the answer is yes, what are the details of the schemes and how are they competitive and cheaper compared to fixed line services?

SHRI ARUN SHOURIE: Sir, yes, various schemes have been launched over the time. I will give the details. There are ten or fifteen of them. I will get the details and supply them.

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने बहुत-सी नीतिगत बातें बताईं और बहुत सी फैसले की बातें कहीं और आगे भी आने की बात कही। श्रीमन्, प्रश्न यह है कि "कारवां क्यों लुटा।" श्रीमन् लाखों की तादाद में इनके टेलीफोन कटते जा रहे हैं क्योंकि इनकी सर्विस संतोषजनक नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस दौरान कितने देहातों, कितने कस्बों और महानगरों में आपके टेलीफोन कटे? क्या इसका कारण केवल असंतोषजनक सर्विस है और उस असंतोष को दूर करने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री सभापति: संख्या बताने के लिए तो नोटिस चाहिए, असंतोष को दूर करने के लिए कुछ कह सकते हो तो कह दीजिए।

श्री अरुण शौरी: सर, बहुत से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। टी.आर.ए.आई. की भी गाइडलाइंस हैं। इससे बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. कंसर्न्ड हैं। ...(**व्यवधान**)...सर, कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसेकि तकरीबन उन्होंने फार रजिस्टरिंग कम्प्लेन्ट्स 1300 सेंटर्स बनाए हैं। वे मॉनीटरिंग करते हैं कि टेलिफोन कम्प्लेंट कब आई और कितनी देर में उसको सॉल्व किया गया। मगर आप देखिए कि माइग्रेशन एक अलग चीज है और टर्मिनेशन ऑफ कनेक्शन दूसरी चीज है। सर, कई बार ऐसा होता है कि बिल पे न किए जाएं तब भी लोगों की लाइनें काटी जाती हैं और काटनी भी चाहिए। सर, एक चीज अगर आपकी इजाजत हो तो कह दूं। एन.टी.पी. 99 के समय में यहां नहीं था, NTP 1999 was also subsequently supplied to the Parliament. मुझे बताया गया। हालांकि मैंने उसे वैरिफाय नहीं किया, मगर वह डिस्कशन हुआ था। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जब चाहें हमारे नए टेलिफोन स्टेप्स के बारे में मैं बात करने के लिए तैयार हूं।